खंड: 7, अंक: 4 अप्रैल 2024 RNI- DELHIN/2021/84711

ISSN- 2584-2803 (Print)

संश्लेषण

सी जी एस मासिक पत्रिका

लोकसभा 2024: जनभावनाएँ तथा संभावनाएँ

Aiming High, Touching Sky

सी जी एस

वैश्विक अध्ययन केंद्र

(पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र)

दिल्ली विश्वविद्यालय

संपादक

प्रोफेसर सुनील कुमार

निदेशक, वैश्विक अध्ययन शोध केंद्र (पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र, डीसीआरसी) एआरसी बिल्डिंग गुरु तेग बहादुर मार्ग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007

ई-मेल आई डी: director@cgs.du.ac.in

प्रोफाइल लिंक: https://cgs.du.ac.in/directorMessage.html

संपादक मंडल

डॉ रमेश कुमार भारद्वाज

सहायक आचार्य, सरकारी पी.जी कॉलेज, जीवाजी विश्वविद्यालय, श्योपुर पाली रोड, मध्य प्रदेश, पिन कोड-476337
संयुक्त निदेशक, वैश्विक अध्ययन शोध केंद्र (पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र, डीसीआरसी) एआरसी बिल्डिंग गुरु तेग बहादुर मार्ग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007

ई-मेल आई डी: rkbhardwaj1@cgs.du.ac.in

प्रोफाइल लिंक: https://www.mphighereducation.nic.in

डॉ महेश कौशिक

सहायक आचार्य, श्री अरबिंदो कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, शिवालिक, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017
अध्येता, वैश्विक अध्ययन शोध केंद्र (पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र, डीसीआरसी) एआरसी बिल्डिंग गुरु तेग बहादुर मार्ग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007

ई-मेल आई डी: mkaushik@cgs.du.ac.in

प्रोफाइल लिंक: https://www.aurobindo.du.ac.in

डॉ संध्या वर्मा

एसोसिएट प्रोफेसर, श्यामलाल कॉलेज (सांध्य), दिल्ली विश्वविद्यालय, जी. टी. रोड, शाहदरा, दिल्ली-110032
अध्येता, वैश्विक अध्ययन शोध केंद्र (पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र, डीसीआरसी) एआरसी बिल्डिंग गुरु तेग बहादुर मार्ग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007

ई-मेल आई डी: sverma@shyamlale.du.ac.in

प्रोफाइल लिंक: https://shyamlale.du.ac.in/wp-content/uploads/2021/11/sandhya-Verma-Political-Science.pdf

डॉ अभिषेक नाथ

सहायक आचार्य, एमएलटी कॉलेज, सहरसा; बी एन मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, बिहार।

ई-मेल आई डी: tuesdaytrack@gmail.com

प्रोफाइल लिंक: https://bpsm.bihar.gov.in/Assets2022/AssetDetails.aspx?P1=2&P2=12&P3=239&P4=3

© सीजीएस2024

संश्लेषण

लोकसभा 2024: जनभावनाएं तथा संभावना

अनुक्रमिका

संपादकीय

1. लोकसभा चुनाव 2024 – भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चुनावी घोषणापत्रों का एक विश्लेषण – रमेश चौधरी 1–9
2. चुनाव 2024: समावेशी और नैतिक नेतृत्व के लिए प्रयास – दृष्टि साह 10–14
3. लोकसभा 2024 के चुनावी घोषणापत्रों का तुलनात्मक अध्ययनः प्रमुख योजनाओं व दृष्टिकोण का आकलन – सृष्टि 15–18
4. जनता की भावनाएं एवं चुनावी रणनीतियाँ – नीलम 19–22
5. लोकसभा 2024: जनभावनाएँ तथा संभावनाएँ – एलिन 23–27

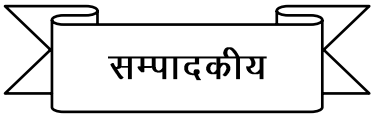

सम्पादकीय

निरंतरता, गुणवत्ता एवं महत्ता पर केन्द्रित सामरिक वाद–विषयों पर युवा शोधार्थियों से लेख आमंत्रण एवं प्रकाशन समसामयिक सामाजिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण चुनौती रहो है। प्रकाशन के इन महत्वपूर्ण सरोकारों और चुनौतियों के आलोक में वैश्विक अध्ययन केंद्र अपनी मासिक पत्रिका, संश्लेषण के 69वें अंक को पाठकों के समक्ष प्रेषित करते हुए अत्यंत हर्ष और उल्लास का अनुभव कर रहा है। पाँच वर्षों से प्रकाशन की इस अकादमिक यात्रा में केंद्र एक परिवार के रुप में समस्त शोधार्थियों, शिक्षार्थियों एवं विद्यार्थियों के सामूहिक प्रयासों से सामाजिक विज्ञान के प्रति अपने संकल्पित ध्येय को साकार करता आ रहा है। निरंतरता की इस कडी में संश्लेषण का यह अंश शोध के प्रति हमारी प्रतिबद्धता एवं दृढ़निश्चतता को प्रदर्शित करने का ही एक सामान्य प्रयास है।

2024 के लोकसभा चुनावों से पूर्व, लोकसभा चुनाव 2024 भारतीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा, जहाँ विभिन्न राजनीतिक दलों की रणनीतियाँ व जनता की अपेक्षाएँ एक नई दिशा में परिवर्तित हो सकती हैं। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी (भा.ज.पा.) केंद्र में सत्ता में है, किंतु आगामी चुनाव में विपक्ष के दलां द्वारा गठबंधन की संभावना, विशेषकर कांग्रेस अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ, चुनावी परिदृश्य को रुचिकर बना सकती है।

जनभावनाओं की बात की जाए तो, महंगाई, बेरोजगारी, व आर्थिक असमानता जैसे विषय आम जनता के मध्य गहन प्रभाव डाल रहे हैं। इसके साथ ही, राज्य व केंद्र सरकार के मध्य विकास कार्यों को लेकर विभिन्न दृष्टिकोण भी सामने आ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभाव को लेकर भिन्न–भिन्न प्रतिक्रियाएँ हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में रोजगार व शिक्षा पर बल दिया जा रहा है।

लोकसभा 2024 में मोदी सरकार की योजनाओं व विपक्षी दलों के गठबंधन की क्षमता पर निर्भर करेगा कि कौन से मुद्दे प्रमुख बनेंगे। अंततः यह चुनाव भारतीय राजनीति के भविष्य को तय करने वाला हो सकता है, जिसमें जनता की उम्मीदें और वास्तविकता एक–दूसरे से टकराएंगी।

राष्ट्रीय स्तर पर विषय की महत्ता तथा राज्य स्तर पर विमर्श की समसामयिकता को ध्यान में रखते हुए केंद्र ने 'लोकसभा 2024ः जनभावनाएँ तथा संभावनाएँ' विषय पर लेख आमंत्रित किये। पाँच उत्कृष्ट लेखों को सम्पादकीय मंडल ने चयनित किया जो आप सभी के समक्ष एक प्रकाशित पत्रिका के रूप में उल्लेखित हो रहे हैं। ये समस्त लेख मौलिक होने के साथ–साथ भारत के लोकतांत्रिक परिदृश्य के बहुआयामी विषयों को भी संबोधित करते हैं। स्वतंत्र चिंतन पर आधारित लेखकों के विचार उनकी रचनात्मकता, सृजनात्मकता एवं मौलिकता को प्रदृशित करने का एक सर्वनिष्ठ प्रयास, प्रयत्न और परिणाम है।

संपादक मंडल मंगलवार, 14 मई 2024

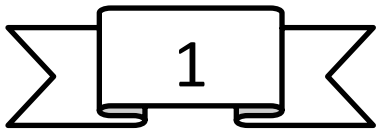

लोकसभा चुनाव 2024– भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चुनावी घोषणापत्रों का एक विश्लेषण

रमेश चौधरी
शोधार्थी, अफ्रीकी अध्ययन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

भारत के चुनावी और राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में चुनावी घोषणापत्र बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्तमान लोकसभा चुनावों में चुनावी घोषणापत्रों की प्रासंगिकता भी महत्वपूर्ण है। इन चुनावों के लिए दोनों प्रमुख राष्ट्रीय भारतीय राजनीतिक दलों भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) ने अपने चुनावी घोषणापत्र जारी किए हैं, जिसमें देश के विकास के लिए अपनी नीतियों, योजनाओं और वादों के बारे में जानकारी दी गई है। बीजेपी ने अपने घोषणापत्र को 'मोदी की गारंटी' और कांग्रेस ने 'न्याय पत्र' नाम दिया है, ये दस्तावेज राजनीतिक दलों के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण और प्रतिबद्धताओं को रेखांकित करने वाले खाका के रूप में कार्य करते हैं।

चुनावी घोषणापत्र – अर्थ एवं विचार

चुनावी घोषणापत्र किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार द्वारा दिया गया चुनाव प्रचार के समय जारी एक सार्वजनिक दस्तावेज या घोषणा है जिसमें विभिन्न मुद्दों पर उनके विचार, उद्देश्य और नीतियां व कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता हैं। चुनावी घोषणापत्र मतदाताओं के लिए राजनीतिक दलां के दृष्टिकोण और वादों का विवरण होता है। घोषणापत्र में आम तौर पर समाज के विभिन्न मुद्दों और सरोकारों को संबोधित करने के उद्देश्य से कार्यक्रम और प्रतिबद्धताएं होती हैं।

घोषणापत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तावित नीतियों और कार्यक्रमों की एक सूची है, जिसके संदर्भ में एक राजनीतिक दल मतदाताओं के समक्ष ये विचार प्रस्तुत करता है कि अगर उसे चुनाव में सत्ता में आने के लिए समर्थन दिया जाता है तो वह उसे लागू करेगा। घोषणापत्र का मेनिफेस्टो है,

"मेनिफेस्टो" शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द मेनिफेस्टम से हुई है, जिसका अर्थ है तथ्यों की एक सूची।

सामान्य रूप से चुनाव से पहले, प्रत्येक राजनीतिक दल या गठबंधन एक आधिकारिक घोषणापत्र जारी करती जो उसके चुनावी अभियान का आधारशिला का काम करती है। चुनावी राजनीति में घोषणापत्र बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे मतदाताओं को यह संप्रेषित करन का मुख्य तरीका हैं कि उन्हें किसी विशेष राजनीतिक दल को अपना मत क्यों देना चाहिए। इसका मुख्य निहितार्थ यह यह है कि घोषणापत्र आम तौर पर एक प्रेरक शैली में लिखे और प्रस्तुत किए जाते हैं जो पाठकों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास करते हैं कि उनमें शामिल नीतियाँ उनके सर्वोत्तम हित में होंगी। चूंकि घोषणापत्रों का उद्देश्य पाठकों को किसी विशेष राजनीतिक दल या उम्मीदवार के लिए मत देने के लिए प्रेरित करना होता है, इसलिए वे अपने घोषणापत्रों में कुछ प्रमुख विचारों, नारों और वाक्यांशों को दोहराते हैं, जिन्हें वे मतदाताओं को अपने चुनावी अभियान से जोड़ना चाहते हैं। ब्रांडिंग या विलक्षण नामकरण आधुनिक राजनीतिक घोषणापत्रों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता है। यह आमतौर पर एक शीर्षक से शुरू होता है जो पार्टी को मतदाताओं के लिए आकर्षक बनाने की कोशिश करता है और अक्सर इसमें राजनीतिक दल की विचारधारा और दल के चुनाव प्रचार के मूल विषय का कोई न कोई संदर्भ जरूर होता है।

चुनावी घोषणापत्र राजनीतिक दलों के लिए मतदाताओं तक अपने दृष्टिकोण और वादों को संप्रेषित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में काम करते हैं। चुनाव के दौरान मतदाताओं को निर्णय लेने के लिए उनके घोषणापत्रों में निहित मुद्दों व विषयों के महत्व और प्रासांगिकता को समझना आवश्यक है।

लोकसभा चुनाव 2024 – मोदी की गारंटी बनाम न्याय पत्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रिकॉर्ड तीसरी बार सत्ता हासिल करने की कोशिश में जुटी भारतीय जनता पार्टी के लिए 370 और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के लिए 400 सीटों का लक्ष्य रखा है। कांग्रेस विपक्ष के इंडिया ब्लॉक का महत्वपूर्ण अंग के रूप में चल रहे लोकसभा चुनाव में लड़कर भाजपा को चुनौती दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को चल रहे लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का घोषणापत्र 'संकल्प पत्र' मोदी की गारंटी 2024 शीर्षक नाम से जारी किया। कांग्रेस पार्टी ने 5 अप्रैल को 'न्याय पत्र' नाम से अपना घोषणापत्र जारी किया। दोनों घोषणापत्रों में विभिन्न मुद्दों और लक्षित समूहों के संबंध में सराहनीय दावे और वादे किए गए हैं। इस लेख का मुख्य उद्देश्य आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक

और सुरक्षा मामलों, महिलाओं, युवाओं और पर्यावरण आदि के लिए नीतियों जैसे विभिन्न पहलुओं पर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के चुनाव घोषणापत्रों को तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत करना है।

- बीजेपी का संकल्प पत्र 'मोदी की गारंटी' बनाम कांग्रेस का न्याय पत्र

2024 के लोकसभा चुनावों के लिए अपने चुनावी घोषणापत्र में, भाजपा और कांग्रेस दोनों ने मतदाताओं के लिए अपनी प्रमुख प्रतिबद्धताओं, वादों और प्राथमिकताओं को रेखांकित किया है। भाजपा का संकल्प पत्र, जिसका शीर्षक "मोदी की गारंटी" है, चार स्तंभों महिलाआं, युवाओं, वंचितों और किसानों के माध्यम से देश के विकास के लिए मोदी की प्रतिबद्धता पर जोर देता है। दूसरी ओर, कांग्रेस पार्टी का घोषणापत्र, जिसका नाम "न्याय पत्र" है और यह राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से प्रेरित है। यह न्याय के पांच स्तंभों (युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय) पर केंद्रित है।

- भारतीय अर्थव्यवस्था और घोषणापत्रों के दावे

दोनों पार्टियों ने अपने घोषणापत्रों में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अपने व्यवहार्य दृष्टिकोण और दावों को रेखांकित किया है। दोनों घोषणापत्रों में आर्थिक मोर्चे पर प्रमुख महत्वपूर्ण दावा अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद के आकार से संबंधित है, भाजपा ने भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का वादा किया है और कांग्रेस ने अगले दस वर्षों में देश की जीडीपी को दोगुना करने का वादा किया है।

बीजेपी के आर्थिक वादे

- भारत के तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की गारंटी
- रोजगार के अवसर बढ़ाने और करदाताओं को समर्थन देने पर ध्यान देने का वादा
- मुद्रास्फीति के निम्न स्तर और आर्थिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता

कांग्रेस के आर्थिक वादे

- अगले दस साल में जीडीपी दोगुनी करने का लक्ष्य
- गिग (फ्रीलांसर) श्रमिकों और असंगठित श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए कानूनों और विनियमों का अधिनियमन।
- मुक्त व्यापार और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के लिए समर्थन।

- युवा मतदाताओं के लिए घोषणापत्र

दोनों ही राजनीतिक दलों ने लोकसभा चुनावों में एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय समूह, युवा मतदाताओं के सरोकारों और आकांक्षाओं को संबोधित करने के लिए अपने घोषणापत्र में एक विशेष समर्पित अनुभाग रखा है।

भाजपा के घोषणा पत्र की युवा मतदाताओं के प्रति प्रतिबद्धता

- परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लागू करना।
- इच्छुक उद्यमियों को समर्थन देने के लिए मुद्रा जैसे क्रेडिट कार्यक्रम का विस्तार, मुद्रा ऋण सीमा को दोगुना करना।
- स्टार्टअप और उद्यमिता के लिए एक प्रवाहकीय वातावरण को बढ़ावा देने की पहल।
- रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की गारंटी।

कांग्रेस के घोषणा पत्र की युवा मतदाताओं के प्रति प्रतिबद्धता

- बेरोजगारी से निपटने के लिए युवा न्याय कार्यक्रम का कार्यान्वयन।
- 25 वर्ष से कम आयु के डिप्लोमा धारकों और कॉलेज स्नातकों के लिए एक वर्ष की प्रशिक्षुता प्रदान करने वाले एक नए प्रशिक्षुता अधिकार अधिनियम की शुरूआत।
- केंद्र सरकार के लगभग 30 लाख रिक्त पदों को भरने की प्रतिबद्धता
- कोविड–19 महामारी के कारण अर्हकारी सार्वजनिक परीक्षा देने में असमर्थ आवेदनकर्ताओं के लिए एकमुश्त राहत।

- घोषणापत्र में कृषक और कृषि

दोनों दलों ने किसानों को एक महत्वपूर्ण वोट बैंक के रूप में पहचानते हुए उनसे वादे किए हैं।

भाजपा के कृषकों और कृषि संबंधी वादे–

- तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से पीएम फसल बीमा योजना को मजबूत बनाना।
- समय–समय पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाने की प्रक्रिया जारी।
- कषि संबंधी मुद्दों के लिए त्वरित और अधिक सटीक मूल्यांकन, बीमा का त्वरित भुगतान और त्वरित शिकायत समाधान सुनिश्चित करना।

कांग्रेस के कृषकों और कृषि संबंधी वादे–

- सरकार द्वारा प्रतिवर्ष घोषित एमएसपी की कानूनी गारंटी, जैसा कि स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश की थी।

• कषि ऋण आवश्यकताओं और ऋण सहनशीलता का आकलन करने के लिए कृषि वित्त पर स्थायी आयोग की स्थापना।

- राष्ट्रीय सुरक्षा पर घोषणापत्रों के दावे

दोनों दलों ने अपने घोषणापत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को संबोधित किया है। और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित इन दावों की समकालीन भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण प्रासंगिकता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े भाजपा के वादे

• भारत की सीमा पर बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी।

• सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और केंद्रीय पुलिस बल को आधुनिक हथियारों और प्रौद्योगिकी से लैस करना।

राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कांग्रेस के वादे

• अग्निपथ योजना का समापन

• एक व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी करना।

• पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के आदेश के अनुसार वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) का कार्यान्वयन।

• पारदर्शिता और सैन्य सहमति सुनिश्चित करने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) की नियुक्ति की प्रक्रिया का संस्थागतकरण

- महिला मतदाताओं के लिए घोषणापत्र में वादे

लगभग 96-8 करोड़ भारतीय 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान करने के पात्र हैं। इनमें से 49-7 करोड़ पुरुष, 47-1 करोड़ महिलाएं और 48000 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। महिला मतदाता चुनावी नतीजों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और दोनों पार्टियों ने उनकी समस्याओं और चिंताओं को दूर करने के लिए वादे किए हैं। इन लोकसभा चुनावों में महिला मतदाता राजनीतिक दलों का भविष्य तय करने में महत्वपर्ण भूमिका निभा रही हैं।

महिला मतदाताओं के लिए भाजपा के वादे दृ

• 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनने के लिए सशक्त बनाना।

- महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर केंद्रित स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार।
- महिलाओं के लिए संसदीय और विधान सभाओं में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए महिला आरक्षण विधेयक का व्यवस्थित कार्यान्वयन।

महिला मतदाताओं के लिए कांग्रेस के वादे

- महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ, प्रत्येक गरीब भारतीय परिवार को बिना शर्त नकद हस्तांतरण के रूप में प्रति वर्ष 1 लाख रुपये प्रदान करना
- 2025 से महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की नौकरियों में 50% आरक्षण।
- प्रत्येक जिले में कम से कम एक सावित्रीबाई फुले छात्रावास के साथ, कामकाजी महिला छात्रावासों की संख्या दोगुनी करना।

- वरिष्ठ नागरिकों के लिए घोषणापत्र में वादे

दोनों राजनीतिक दलों ने अपने घोषणापत्रों में वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों और चिंताओं, विशेषकर स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के संबंध में योजनाओं और पहलों को शामिल किया है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए भाजपा के वादे

- 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को समायोजित करने के लिए आयुष्मान भारत योजना का विस्तार।
- पवित्र तीर्थयात्रा करने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाजनक सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के साथ सहयोग।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए कांग्रेस के वादे

- विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 को सख्ती से लागू करना।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए सार्वजनिक परिवहन (रेलवे एवं सड़क परिवहन) में यात्रा रियायत की बहाली।
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए पेंशन योगदान को बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति माह किया जायेगा।

- घोषणापत्रों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र

कोविड–19 महामारी के बाद स्वास्थ्य संबंधी मामले धीरे–धीरे अधिक महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा बन गए हैं। इसीलिए दोनों राजनीतिक दलों ने अपने घोषणापत्रों में स्वास्थ्य सेवा को संबोधित किया है।

स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर भाजपा के वादे

- गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) नेटवर्क को मजबूत करना।
- मजबूत स्वास्थ्य सेवा के लिए पीएम–आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (च्ड–।ठभ्प्ड) का विस्तार
- सस्ती दवा के लिए पीएम–जन औषधि केंद्र नेटवर्क का विस्तार।
- ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए आयुष्मान भारत कवरेज।

स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर कांग्रेस के वादे

- सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए 25 लाख रुपये तक कैशलेस बीमा के राजस्थान मॉडल को अपनाना
- 2028–29 तक कुल व्यय का 4% हासिल करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल बजट में विकासशील वृद्धि।
- चिकित्सा परीक्षण, उपचार, दवा और पुनर्वास सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल का आश्वासन।

- घोषणापत्रों में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित मामले

पिछले कुछ वर्षों में, पर्यावरणीय मुद्दे राजनीतिक घोषणापत्रों में शामिल होने लगे हैं। दोनों राजनीतिक दलों ने पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रति अपनी विभिन्न प्रतिबद्धताओं को रेखांकित किया है।

पर्यावरण से जुड़े मामलों पर भाजपा के दावे

- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत निर्दिष्ट परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों की उपलब्धि और रखरखाव करना
- चरणबद्ध पहल के माध्यम से प्रमुख नदियों के स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार।

पर्यावरण से जुड़े मामलों पर कांग्रेस के दावे

- वायु प्रदूषण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) को मजबूत करना।

- पर्यावरण मानकों और योजनाओं को लागू करने के लिए एक स्वतंत्र पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण की स्थापना।

भाजपा के घोषणापत्र में मोटे तौर पर उन्हीं नीतियों और कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जिन्हें वह पिछले दशक में लागू कर रही है। भाजपा के घोषणापत्र का मुख्य ध्यान मुद्रास्फीति नियंत्रण, वृहद स्थिरता, राजकोषीय समझदारी, विनिर्माण पर जोर, बुनियादी ढांचे का निर्माण आदि पर है। जबकि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणापत्र में गरीबों को 1 लाख रुपये नकद हस्तांतरण प्रदान करने के वादे के साथ आर्थिक नीतियों में बदलाव, एक राष्ट्रव्यापी सामाजिक–आर्थिक और जातिगत जनगणना और उस जनगणना के आंकड़ों के आधार पर सकारात्मक कार्रवाई का वादा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जाति वर्गों के लिए आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत बढ़ाना का वादा किया है।

रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे, सामाजिक सुरक्षा, कृषि से संबंधित सुधार जैसे मुद्दों पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच अंतर की तुलना में अधिक समानताएं हैं, कम से कम घोषणापत्र पर तो यही बात लाग् होती है। दोनों राजनीतिक दलों के बीच प्रमुख अंतर समान नागरिक संहिता और नागरिकता संशोधन अधिनियम आदि जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों के प्रति उनके दृष्टिकोण में है।

भाजपा का घोषणापत्र परिवर्तन की बजाय "निरंतरता" की ओर अधिक झुका हुआ है, क्योंकि भाजपा अपने 10 वर्षों के प्रदर्शन के ट्रैक रिकॉर्ड पर आश्वस्त हो सकती है, जिससे अगले पांच वर्षों में भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में मदद मिलने की उम्मीद है। घोषणापत्रों का तुलनात्मक विश्लेषण करने पर, भाजपा बहुमत के साथ सत्ता में वापस आने के प्रति बहुत आश्वस्त दिखती है, यही कारण है कि भाजपा के घोषणापत्र का चरित्र नीतियों और कार्यक्रमों की निरंतरता को दर्शाता है। जबकि कांग्रेस अपने घोषणापत्र में सत्ता में आने के लिए हर संभव प्रयास करने का वादा कर रही है।

सन्दर्भ सूची

- Bharatiya Janta Party. (2024). *Modi Ki Guarantee 2024.* New Delhi: BJP
- Indian National Congress. (2024). *Nyay Patra.* New Delhi: AICC
- Mukerjee, Shikha. (2024). *Lok Sabha elections 2024: Poll manifestos and Politics of IOUs.* Delhi: Deccan Herald
- Mahajan, Ashwini. (2024). *Comparing Manifestos of Political parties in Lok Sabha elections 2024: Manifestation of Mission Vs Confusion.* New delhi: Organiser

♦♦♦♦♦

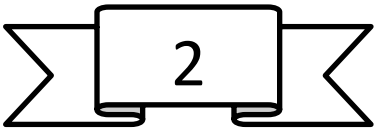

चुनाव 2024: समावेशी और नैतिक नेतृत्व के लिए प्रयास

दृष्टि साह

पीएचडी शोधार्थी, दिल्ली विश्वविद्यालय

लोकसभा चुनाव 2024 के भारतीय परिप्रेक्ष्य को देखते हुए, लोकतंत्र के सार को बनाए रखने के लिए नए आयाम, दिशा और विकास की खोज की जा सकती है। इन वर्षों में, भारतीय लोकतंत्र ने जाति–आधारित राजनीति से मुद्दा–आधारित राजनीति, महिला सशक्तिकरण से महिलाओं क नेतृत्व वाले विकास, एक पार्टी के प्रभुत्व से गठबंधन के नेतृत्व वाली पार्टी प्रभुत्व तक विविध परिवर्तन देखे हैं। दूसरे लोकतांत्रिक उत्थान के वर्षों से, लोकतंत्र ने विभिन्न समुदायों को मान्यता देने से लेकर दलित वर्गों की समावेशी भागीदारी तक अपनी आधार संरचना को गहरा कर दिया है। सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया होने के नाते, लोकतांत्रिक राजनीति चुनावों के सभी स्तरों पर प्रकृति में गतिशील है। लगभग 96 करोड़ से अधिक मतदाताओं के पंजीकृत होने के साथ, भारत के जनसांख्यिकीय पैमाने को निर्वाचन क्षेत्रों की प्रचुर संख्या में विभाजित किया गया है, प्रत्येक का नेतृत्व एक विशेष राजनीतिक दल के प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है। निश्चित रूप से, भारतीय चुनाव लोकतंत्र की अभिव्यक्ति रहे हैं जो इसकी जटिलताओं, विविधताओं और जातीयताओं से लेकर इसके सिद्धांतों की गहराई तक जा रहे हैं। इसलिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेताओं का राजनीतिक नेतृत्व और इसकी विशेषता इस लेख का मुख्य घटक है।

राजनीतिक नेतृत्व

भारतीय चुनावों में नेतृत्व की घटना लोकतांत्रिक प्रणाली के शासन को तय करने में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करती है। एक करिश्माई नेता अपने भाषणों, दृष्टि और व्यवहार कृत्यों के माध्यम से लोगों को समझाने की क्षमता दिखाता है। सत्ता के प्रतिस्पर्धी खेल में, नेतृत्व का तत्व इतना महत्वपूर्ण होता है कि नेताओं को देश के भविष्य के रूप में माना जाता है। एक परिप्रेक्ष्य के रूप में राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका हमारे दिमाग को तीन महत्वपूर्ण विशेषताओं को

देखने के लिए प्रेरित करती है जो एक राजनीतिक नेता के पास होनी चाहिए। राजनीतिक नेतृत्व की पहली विशेषता दो मुख्य कारणों से संवाद करने की मूल इच्छा है य संचार कौशल विकसित करना और जनता को उनके पक्ष में खुश करना। इस प्रकार, इसके परिणामस्वरूप संचार और आत्मविश्वास की प्रभावशीलता हो सकती है। दूसरे, सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक एक नेता द्वारा अपने अनुयायियों का निर्माण करने और संगठन को मजबूत करने के लिए कहानी सुनाना है। जैसा कि विद्वानों ने ठीक ही कहा है, सही कथन हजार सिद्धांतों के लायक लगता है। सुनाई गई कहानियां मूल्यों के प्रसारण के साथ चिंगारी संदेश को दर्शाती हैं और एक राजनीतिक नेता के ज्ञान और व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित करती हैं। यह सुविधा एक नेता के तर्कसंगत दिमाग, बातचीत करने और जनता की राय को आकार देने और सबसे प्रभावी भाषण देने की क्षमता को रेखांकित करती है। यहां, महत्वपूर्ण हिस्सा सार्वजनिक रूप से शब्दों के वितरण के दौरान काउंटर की गई भावनाओं को चौनलाइज करना है। इसलिए, राजनीतिक नेतृत्व एक संवादात्मक प्रयास है जो काफी हद तक सार्वजनिक सभाओं में सुनाई गई कथाओं द्वारा आकार दिया जाता है। राजनीतिक संचार के दृष्टिकोण से, नेतृत्व सबसे प्रभावी होता है, इसलिए मानव अनुभव के मूल में कोई यह कह सकता है कि सामान्य रूप से नेतृत्व और विशेष रूप से राजनीतिक नेतृत्व प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति के बजाय एक कार्रवाई है।

इस लेख में, मैं नेतृत्व के दो रूपों के बारे में बात करना आवश्यक है जो लोकतांत्रिक राजनीति के एक महत्वपूर्ण पहलू पर जोर देते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव समावेशी और नैतिक नेतृत्व के लिए प्रयास करते हैं जो कि लोकतंत्र को गहरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

समावेशी नेतृत्व

नेतृत्व का यह रूप शासन का एक तरीका है जो लिंग, धर्म, नस्ल, जाति आदि जैसे समाज के विभिन्न क्षेत्रों का सक्रिय रूप से प्रतिनिधित्व करना चाहता है। समावेशी नेतृत्व का मूल विचार स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीकों से लोगों को समान अवसर को बढ़ावा देना है। यह प्रणाली को प्रतिनिधित्व, भागीदारी और निर्णय लेने की प्रक्रिया में एकरूपता सुनिश्चित करने का अधिकार देता है। 75 साल की चुनावी यात्रा ने हाशिए के क्षेत्रों के बहिष्कार के अंतर को कम कर दिया है और सबाल्टर्न के दायरे को बढ़ा दिया है। समावेशी नेतृत्व की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं।

सहानुभूतिः यहां के नेता हाशिए के क्षेत्रों की समस्याओं और चिंताओं को सुनते हैं। वे अपनी भलाई के लिए काम करने के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाते हैं।

लचीलापनः एक समावेशी नेता अपने विचारों में विविधता लाने के लिए कई प्रकार के दृष्टिकोणों पर विचार करता है। माइंड मैपिंग कौशल यहां मजबूत हो जाता है क्योंकि एक नेता बहुआयामी तरीके से सोचता है और कार्य करता है।

समानताः एक अच्छा नेता वह है जो दूसरों को समान अवसर देता है और एक मजबूत टीम बल बनाने की कोशिश करता है। वह किसी भी प्रकार के भेदभाव के बावजूद दूसरों को सभी के साथ, सभी के लिए वृद्धि और विकास सुनिश्चित करने का मौका देता है।

जवाबदेहीः यह एक नेता की जिम्मेदारी है कि वह अपने कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखे। यह टीम के सदस्यों के पूर्ण सहयोग और समन्वय के साथ समावेशी वातावरण को बढ़ावा देना है।

इसलिए, हम कह सकते हैं कि समावेशी नेतृत्व लोकतंत्र के निचले स्तर पर अधिक कुशल हो सकता है जो अधिक सुसंगत तरीके से पारदर्शिता और जवाबदेही लाएगा। हालांकि, राष्ट्रीय स्तर पर एक समावेशी दृष्टिकोण वाले नेता स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्यों में टीम के सदस्यों के नवाचारों और रचनात्मकता को गले लगा सकते हैं।

नैतिक नेतृत्व

नैतिक नेतृत्व का रूप तब देखा जाता है जब नेतृत्व का करिश्मा विश्वास और अच्छे कार्यो के सम्मान के महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर तैयार या विकसित किया जाता है। नैतिक नेतृत्व अपने प्रमुख सिद्धांतों को मनोबल के तरीके से अभ्यास करने का आधार बनाता है। जमीनी स्तर पर नैतिकता के प्रसंस्करण में शामिल प्रथाओं के आधार को समझने के लिए, हमें इस तरह की कुछ विशेषताओं को देखना चाहिएय

सम्मानः एक नेता में सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता दूसरों के अधिकारों, गरिमा और व्यक्तित्व का सम्मान करना है। एक अच्छा नेता तभी अच्छा होने का दावा कर सकता है जब कोई दूसरों के अपनेपन और राष्टोय पहचान का सम्मान करना जानता हो।

विश्वसनीयताः एक नैतिक नेतृत्व में, विश्वास सिद्धांत नेतृत्व की प्रक्रिया में आधारशिला लेता है। नेतृत्व का यह गुण एकमात्र तत्व है जो नेता को किसी देश में अपने नागरिकों के लिए विश्वसनीय बनाता है। दुनिया भर में उनके लिए किए गए नेता के वादों के विश्वास में अपने चुने हुए नेता के लिए विश्वास विकसित होता है।

निष्पक्षताः एक राष्ट के नेता को नैतिक माना जाता है जब वह वास्तविक आम आदमी और उनकी सख्त जरूरतों को जानता है। वे आम आदमी की जरूरतों और कल्याण के आधार पर निर्णय लेते हैं। इसमें सही वस्तुओं के साथ समुदायों और नागरिकों की सेवा करने में एक इक्विटी और पारदर्शिता शामिल है।

स्थिरताः एक कुशल नेतृत्व गुणवत्ता एक राष्ट के हर पहलू में भविष्य के परिप्रेक्ष्य के लिए आवश्यक है। वे लोकतांत्रिक राजनीति में दीर्घायु, हितधारकों, राजनीतिक लाभ के लिए प्रयास करते हैं।

लोकप्रियता और शक्ति से आगे बढ़ते हुए, नैतिक नेतृत्व अपने नागरिकों और समुदायों के प्रति दृढ़ विश्वास के लिए प्रयास करता है। नेता अपने मूल्यों, जवाबदेही और अखंडता के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। संघीय स्तर के चुनावों के नेताओं में एक नैतिक नेतृत्व की कल्पना की जा सकती है। चूंकि, वे नागरिकों के साथ एक मजबूत संबंध बनाने में विश्वास करते हैं और उनके लिए लगातार काम करने का वादा करते हैं।

समाप्ति

चुनावों में नेतृत्व के एक विषयगत विश्लेषण से राजनीतिक नेतृत्व के विभिन्न घटकों का पता चलता है जिन्हें मोटे तौर पर नैतिक और समावेशी नेतृत्व के रूप में समझा जाता है। किसी भी देश में राजनीतिक नेतृत्व की प्रक्रियाओं में उपर्युक्त कुछ विशेषताएं शामिल होंगी जो नेतृत्व पहलू में महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के रूप में भी कार्य करती हैं। नेतृत्व के दो उप विषयों ने चार प्रमुख श्रेणियों को कम कर दिया है जो एक नेता की समावेशिता और नैतिकता को दर्शाता है। उन्हें सबसे पहले समझा जा सकता है, एक नेता अपने नागरिकों से वादे करता है, वादों के आधार पर नागरिक अपने प्रतिनिधियों को जीवन की बेहतरी के लिए नियुक्त करते हैं। नागरिकों के वोट देने के बाद चुने हुए प्रतिनिधि के बारे में एक जनादेश जारी किया जाता है। अंत में, नेतृत्व की प्रक्रिया एक नेता और उसके नागरिक के कारण–प्रभाव संबंध का विश्लेषण करने की कार्य–कारण प्रक्रिया के साथ समाप्त होती है। इसलिए, किसी भी चुनाव में, नेतृत्व की प्रक्रिया समग्र रूप से वादों के साथ बहती है और उस चुनाव के कारण समाप्त होती है। इसलिए, एक नेता नेतृत्व प्रक्रिया के सभी प्रमुख और छोटे सिद्धांतों को शामिल कर एक मजबूत और उपयोगी नेतृत्व गुणों के लिए प्रयास करता है।

संदर्भ सूची

- Dion, Leon (1968). "The Concept of Political Leadership: An Analysis". Canadian, Journal of Political Science. Vol. 1, No. 1.
- Sisodia, Yatindra S & Chattopadhyay, Pradip (eds) (2023). Political Communication in Contemporary India: Locating Democracy and Governance. New York: Routledge.
- Elgie, Robert (1995). Political Leadership in Liberal Democracies. London: Macmillan Press.

♦♦♦♦♦

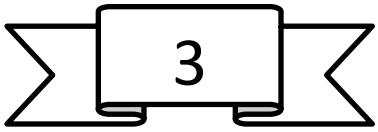

लोकसभा 2024 के चुनावी घोषणापत्रों का तुलनात्मक अध्ययनः प्रमुख योजनाओं व दृष्टिकोण का आकलन

सृष्टि

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

लोकसभा 2024 का चुनाव भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है, जहाँ देश के भविष्य के निर्णय को लेकर मतदाता निर्णायक भूमिका में होंगे। इस चुनाव में प्रत्येक राजनीतिक दल अपने घोषणापत्र (Manifesto) के माध्यम से जनता से जुड़ने व अपनी नीतियों को प्रस्तुत करने की पूर्ण प्रयास कर रहा है। घोषणापत्र केवल चुनावी वादों का संग्रह नहीं होते, अपितु ये उस पार्टी के दृष्टिकोण, प्राथमिकताओं व राजनीतिक रणनीतियों को दर्शाते हैं। इस आलेख में हम यह विश्लेषण करेंगे कि लोकसभा 2024 के घोषणापत्रों के आधार पर किस दल की जीत की संभावनाएँ अधिक हैं।

1. भारतीय जनता पार्टी (BJP) का घोषणापत्रः 'विकास व सुरक्षा'

भा.ज.पा. (BJP) का घोषणापत्र हमेशा से ही विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा पर बल देने वाला रहा है। 2024 के लिए BJP ने अपनी प्राथमिकताएँ स्पष्ट की हैं। इस बार भी उनका जोर प्रमुख रूप से आर्थिक सुधारों, डिजिटल इंडिया, हर नागरिक को सरकारी सेवाओं की उपलब्धता, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, और भारत को वैश्विक शक्ति बनाने की दिशा पर रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी ने अपनी घोषणापत्र में कुछ प्रमुख वादे किए हैं।

- आर्थिक सुधारः देश में रोजगार सृजन, छोटे व मध्यम उद्योगों को बढ़ावा, तथा कृषि क्षेत्र में तकनीकी सुधार।

- राष्टोय सुरक्षाः आतंकवाद और सीमा सुरक्षा पर कड़ी कार्रवाई, भारत को एक मजबूत रक्षा राष्ट बनाना।

- महिला सशक्तिकरणः महिलाओं के लिए अधिक सरकारी योजनाएं व रोजगार के अवसर।
- स्वास्थ्य और शिक्षाः स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच बढ़ाना।

बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में अपने पिछले कार्यकाल की उपलब्धियों की व्याख्या करते हुए 'विकास' को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है। साथ ही, उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा व हिंदुत्व के मुद्दे को भी प्रमुखता दी है। यह दृष्टिकोण भाजपा के परंपरागत वोट बैंक, विशेषकर शहरी आर मध्यवर्गीय मतदाताओं के मध्य अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए उपयुक्त है। तथापि, महंगाई व बेरोजगारी जैसे मुद्दे भाजपा के लिए चुनौती हो सकते हैं, जो विपक्ष के लिए चुनावी मुद्दे बन सकते हैं।

2. कांग्रेस का घोषणापत्रः 'समानता और न्याय'

कांग्रेस ने 2024 के चुनाव के लिए अपनी घोषणापत्र में 'समाजवाद, समानता और न्याय' के सिद्धांत को प्राथमिकता दी है। पार्टी का दावा है कि उसकी सरकार किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं व महिलाओं के लिए विशेष योजनाएँ लेकर आएगी। इसके अतिरिक्त, कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में निम्नलिखित प्रमुख वादे किए हैं।

- रोजगार व आर्थिक संकटः कांग्रेस ने वादा किया है कि वह देश में 25 लाख सरकारी नौकरिया प्रदान करेगी तथा युवाओं के लिए एक विशेष योजना बनाएगी।
- कृषि व कृषकों के मुद्दः किसान आय बढ़ाने व कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए कांग्रेस ने एक व्यापक योजना प्रस्तुत की है, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी सम्मिलित है।
- महंगाई पर काबूः कांग्रेस महंगाई की दर को नियंत्रित करने के लिए योजनाएं लाने का वादा करती है।
- गरीबों के लिए योजनाएंः प्रत्येक निर्धन परिवार को आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से और अधिक लाभ पहुंचाने की योजना।

कांग्रेस के घोषणापत्र में केंद्रित विषयों में सामाजिक न्याय व समानता हैं, जो विशेष रूप से दलितों, पिछड़ों व अल्पसंख्यकों के मध्य लोकप्रिय हो सकते हैं। कांग्रेस की इस घोषणा के बाद यह साफ हो जाता है कि वह गरीबों और कमजोर वर्गों के लिए अपनी योजनाएँ लाने के लिए

प्रतिबद्ध है। तथापि, कांग्रेस को सत्ता में लौटने के लिए विपक्षी गठबंधन की एकता व चुनावी रणनीति की सफलता की आवश्यकता होगी।

3. अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी (SP) का घोषणापत्रः 'निर्धनता व बेरोजगारी के विरुद्ध संघर्ष'

समाजवादी पार्टी (SP) का घोषणापत्र विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के लिए अहम होगा। पार्टी ने इस बार युवाओं, कृषकों व महिलाओं के लिए कई प्रमुख वादे किए हैं। उनका घोषणापत्र निम्नलिखित है।

- नौकरी व शिक्षाः बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए सरकारी नौकरिया बढ़ाना, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना।
- कृषि सुधारः कृषकों को बेहतर MSP और कर्जमाफी की योजनाएं।
- महिला सुरक्षाः महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा बल गठित करना व उन्हें सशक्त बनाना।
- सामाजिक न्यायः समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक व आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना।

समाजवादी पार्टी अपने घोषणापत्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ बनाने का प्रयास कर रही है। विशेष रूप से उनके कृषक व युवा वर्ग के लिए किए गए वादे उन्हें चुनावी सफलता दिला सकते हैं। तथापि, पार्टी को राज्य में भाजपा व कांग्रेस के गठबंधन से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है।

4. आम आदमी पार्टी (AAP) का घोषणापत्रः 'सुधार व पारदर्शिता'

आम आदमी पार्टी (AAP) का घोषणापत्र विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष पर आधारित है। पार्टी ने अपने घोषणापत्र में निम्नलिखित वादे किए हैंः

- शिक्षा व स्वास्थ्यः हर राज्य में स्कूलों व अस्पतालों की स्थिति में सुधार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाना।

- पारदर्शिता और भ्रष्टाचार विरोधी कानूनः भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सख्त कदम उठाना।

- बिजली और पानी की सुविधाः देशभर में सस्ती बिजली व पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना।

आम आदमी पार्टी ने सदैव दिल्ली के मॉडल को बढ़ावा दिया है, और उनका घोषणापत्र इसी मॉडल को शेष राज्यों में लागू करने का वादा करता है। पार्टी की यह रणनीति उन्हें विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में लाभकारी सिद्ध हो सकती है, जहाँ शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं का प्रशन मुख्य मुद्दा हो सकता है। तथापि, भाजपा और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों के मुकाबले आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर जीत की राह में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

5. निष्कषः किस दल की जीत की संभावनाएँ हैं?

लोकसभा 2024 के चुनाव में किस दल की जीत की संभावनाएँ अधिक हैं, यह केवल घोषणापत्रों से निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वास्तविक चुनावी परिणाम कई अन्य कारकों पर निर्भर करते हैं, जैसे क्षेत्रीय समीकरण, स्थानीय मुद्दे, गठबंधन और उम्मीदवारों की छवि।

भारतीय जनता पार्टी (BJP) का दावा 'विकास' व 'राष्ट्रीय सुरक्षा' पर आधारित है, जो उन्हें बड़े शहरी और मध्यवर्गीय वोटरों में सुदृढ़ बना सकता है। कांग्रेस व समाजवादी पार्टी अपने घोषणापत्र के माध्यम से निर्धनों, किसानों व युवाओं के लिए व्यापक योजनाएँ प्रस्तुत कर रही हैं, जो ग्रामीण इलाकों व पिछड़े वर्गों में प्रभाव डाल सकती हैं। आम आदमी पार्टी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर बल दिया है, जो शहरी मतदाताओं को आकर्षित कर सकता है।

अंततः, घोषणापत्र केवल एक दिशा का संकेत होते हैं। जीत की संभावनाएँ इस पर निर्भर करेंगी कि राजनीतिक दल अपनी घोषणाओं को कितनी सशक्त माध्यम से लागू कर पाते हैं और वे जनता के विश्वास को कितना जीत पाते हैं।

♦♦♦♦♦

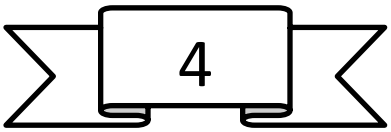

जनता की भावनाएं एवं चुनावी रणनीतियाँ

नीलम

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

भारत में लोकसभा चुनाव हर पाँच वर्ष में होते हैं, जो लोकतंत्र की महत्ता और जनता की शक्ति को दर्शाते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आकर खड़ा है। इस चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के मध्य संघर्ष शीघ्र हो चुका है व जनता की भावनाएँ भी इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। 2024 का चुनाव न केवल देश की आंतरिक राजनीति को प्रभावित करेगा, अपितु अंतराष्ट्रीय राजनीति में भी इसके दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं।

लोकसभा 2024 का संदर्भ

लोकसभा 2024 चुनाव भारतीय लोकतंत्र की स्थिरता और प्रगति को निर्धारित करेगा। वर्तमान में, भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) केंद्र में सत्तारूढ़ है, व उनके नेतृत्व में सरकार की नीतियाँ, चाहे वह आर्थिक सुधार हों या विदेश नीति, उन्होंने देश को एक नई दिशा दी है। किंतु इसके साथ ही विपक्षी दलों का गठबंधन भी सरकार के विरुद्ध अपनी रणनीतियाँ बना रहा है, जिससे कि सत्ता में परिवर्तन लाया जा सके।

जनभावनाएँ: चुनाव के आसपास की मानसिकता

लोकसभा 2024 चुनाव के बारे में जनता की भावनाएँ कई पहलुओं से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले, भारतीय समाज में बढ़ती आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, महंगाई और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति ने चुनावी वातावरण को प्रभावित किया है। भाजपा के शासन में कुछ क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव आए हैं, जैसे कि डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री

जन धन योजना। हालांकि, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे जनता के मन में असंतोष उत्पन्न कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, भारतीय जनता पार्टी की ओर से हिन्दू धर्म के प्रति समर्थन व राष्ट्रवाद को लेकर किए गए उपायों ने कुछ वर्गों में सकारात्मक भावनाएँ उत्पन्न की हैं, जबकि विपक्षी दलों का आरोप है कि यह मुद्दे मात्र ध्रुवीकरण के लिए उठाए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप, चुनाव में इन मुद्दों को लेकर मतदाताओं के मध्य दोराय बनी हुई है।

विपक्षी गठबंधन और चुनावी रणनीतियाँ

कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस (TMC), समाजवादी पार्टी (SP), आम आदमी पार्टी (AAP) और अन्य विपक्षी दलों ने मिलकर एक सुदृढ़ विपक्षी गठबंधन बनाने की दिशा में कार्य करना शुरू कर दिया है। इन दलों का उद्देश्य भाजपा को हराना व अपनी राजनीतिक शक्ति को सिद्ध करना है। इन दलों ने भाजपा सरकार के विरुद्ध कई मोर्चों पर आवाज उठाई है, जिनमें महंगाई, बेरोजगारी व मौलिक अधिकारों का उल्लंघन सम्मिलित है।

इस गठबंधन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वे क्षेत्रीय मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। तथापि, विपक्षी दलों के मध्य आंतरिक असहमति व नेतृत्व के विवाद भी एक बड़ी चुनौती हैं। उनके मध्य एकता की कमी और सीटों के बंटवारे पर मतभेद चुनावी रणनीति का प्रभावित कर सकते हैं।

4- आर्थिक मुद्दे: महंगाई और बेरोजगारी

आर्थिक मुद्दे लोकसभा चुनाव 2024 के प्रमुख आकर्षण बन सकते हैं। देश में महंगाई की दर बढ़ी है, जिससे आम जनता के जीवन पर भारी प्रभाव पड़ा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि, खाद्य सामग्री की महंगाई और आवास की बढ़ती कीमतें इन समस्याओं को और जटिल बना रही हैं। इसके अतिरिक्त, युवा वर्ग में बेरोजगारी की समस्या भी गंभीर बनी हुई है, जो एक अहम चुनावी मुद्दा हो सकता है।

कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों ने इन मुद्दों को अपनी चुनावी रणनीति का भाग बनाया है। वे भाजपा सरकार को इन समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए जनता से चुनावी समर्थन प्राप्त करने की प्रयास करेंगे। भाजपा ने अपनी नीतियों को जनहित में बताते हुए विकास को प्रमुख मुद्दा बनाने

का प्रयास किया है, किंतु यह प्रशन बना हुआ है कि क्या जनता आर्थिक संकट के बावजूद उसे समर्थन देगी।

राजनीतिक पार्टियों की संभावनाएँ

भा.ज.पा. (BJP) के लिए, लोकसभा 2024 चुनाव जीतने की संभावना अत्यंत सुदृढ़ दिखती है, क्योंकि उन्होंने अपने शासनकाल में कई बड़े परिवर्तन किए हैं, जैसे आर्थिक सुधार, डिजिटल इंडिया व वैश्विक मंच पर देश का प्रभाव बढ़ाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता भी भाजपा के लिए एक सुदृढ़ स्तंभ है। तथापि, महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की स्थिति जैसे मुद्दों पर विपक्ष निरंतर भाजपा को घेरने में सफल हो रहा है। इसके बावजूद, भाजपा का राष्ट्रीय आधार व उसके समर्थन की ठोस नींव चुनावों में उसकी सफलता को प्रभावित कर सकती है।

विपक्षी गठबंधन की संभावना पर विचार करें तो यह थोड़ा अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उनके लिए सबसे बड़ी समस्या एकजुटता की कमी व सीटों के बंटवारे को लेकर असहमति है। फिर भी, यदि विपक्षी दलों को कोई सशक्त नेता मिल जाता है, तो वे भाजपा को एक गंभीर चनौती दे सकते हैं। कांग्रेस के पास भारत के सबसे पुराने राजनीतिक दल होने के नाते एक बड़ा जनाधार है, जबकि क्षेत्रीय दल जैसे तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, और आम आदमी पार्टी की शक्ति राज्य स्तर पर स्पष्ट है।

सामाजिक मुद्देः धर्म और जातिवाद

भारत में चुनाव सदैव सामाजिक मुद्दों से भी जुड़े होते हैं, विशेषकर धर्म व जातिवाद के संदर्भ में। भाजपा के लिए हिंदुत्व का मुद्दा महत्वपूर्ण है, वहीं विपक्षी दलों ने इसे एक विभाजनकारी एजेंडे के रूप में देखा है। कांग्रेस व अन्य विपक्षी दल इस आरोप का सामना कर रहे हैं कि भाजपा धर्म के आधार पर राजनीति कर रही है, जबकि विपक्ष इसे समानता व सामाजिक न्याय के मुद्दे के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करता है।

जातिवाद भी एक महत्वपूर्ण पहलू है, विशेषकर उत्तर भारत में, जहाँ जाति आधारित राजनीति की महत्ता बहुत अधिक है। क्षेत्रीय दल, जैसे समाजवादी पार्टी व बहुजन समाज पार्टी (BSP), अपने–अपने सामाजिक आधार से चुनावी लाभ प्राप्त करने का प्रयास करेंगे।

निष्कर्ष

लोकसभा 2024 चुनाव भारतीय राजनीति के लिए एक निर्णायक मोड़ हो सकते हैं। भाजपा व विपक्ष दोनों के पास अपनी–अपनी रणनीतियाँ हैं, और चुनावी माहौल में जनता की उम्मीदें भी काफी प्रभावित हो सकती हैं। आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर बहस तेज है, तथा यह चुनाव उस दिशा को निर्धारित करेगा, जिसमें भारतीय राजनीति व समाज आगे बढ़ेंगे।

जनता की भावनाएँ चुनावी रणनीतियों व गठबंधनों को प्रभावित करेंगी, तथा परिणामस्वरूप भारतीय राजनीति का अगला अध्याय लिखा जाएगा। इसलिए, यह चुनाव न केवल राजनीतिक दलों के लिए, अपितु समग्र देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है।

♦♦♦♦♦

5

लोकसभा 2024: जनभावनाएँ तथा संभावनाएँ

एलिन

विद्यार्थी, जीसस एंड मेरी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय

भारतीय लोकतंत्र में लोकसभा चुनाव सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं, जो देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करते हैं। 2019 के लोक सभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए 303 तीन सीटें प्राप्त की थी जबकि कांग्रेस मात्र 52 सीटों पर सिमट गई थी। अब 2024 के चुनावों को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों व जनता के मध्य विचार–विमर्श शीघ्र है कि क्या इस बार कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। हाल के विधानसभा चुनावों के बदलते राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए 2024 का चुनाव न केवल सत्ता के संतुलन को प्रभावित करेगा, अपितु भारतीय राजनीति में नए परिदृश्य के भी निर्मित कर सकता है। ऐसे में यह चुनाव देश की नीतियों शासन प्रणाली व लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।

लोकसभा 2024: जनभावनाओं का बदलता स्वरूप

लोक सभा चुनाव से पहले जनता की सोच और भावनाओं में लगातार बदलाव आते रहते हैं, जो विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कार्यों को से प्रभावित होते हैं। इन बदलावों को समझने के लिए साप्ताहिक या मानसिक सर्वेक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।" लोकनीति–CSDS" और "C– अवजमत" जैसे सर्वेक्षण संस्थानों के आँकड़े यह दर्शाते हैं कि मतदाताओं की प्राथमिकताएं समय के साथ बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए, हाल ही के एक सर्वेक्षण में बेरोजगारी और महँगाई को सबसे अहम मुद्दे बताया गया है, जो यह संकेत देता है कि ये विषय आगामी चुनावों में जनता के निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। इस तरह के सर्वेक्षणों के माध्यम से ही आंकलन किया जा सकता है कि चुनाव से पहले और चुनावी प्रक्रिया के दौरान जनभावनाओं में क्या परिवर्तन हो रहे हैं और इसका चुनावी नतीजों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है।

2024 चुनाव में प्रमुख मुद्देः विकास, बेरोजगारी व सामाजिक समरसता

2024 लोकसभा चुनाव में मतदाता जिन प्रमुख मुद्दों पर सबसे अधिक ध्यान दे रहे हैं, उनमें बेरोजगारी, स्वास्थ्य–सेवाएँ, महंगाई और जातिवाद जैसे सामाजिक पहलू सम्मिलित है। देश में आर्थिक विकास व जनकल्याणकारी योजनाओं की स्थिति भी मतदाताओं के निर्णय को प्रभावित कर सकती है। बेरोजगारी विशेष रूप से एक गंभीर विषय बना हुआ है, क्योंकि युवाओं में नौकरी न मिलने की समस्या निरंतर विचार–विमर्श का केंद्र बनी हुई है।2019 में हुई " नेशनल सैंपल सर्वे (NSS)" रिपोर्ट के अनुसार, 2018–19 हमें भारत की बेरोजगारी दर 6.1ः थी, जो पिछले 45 वर्षों में सबसे अधिक थी। यह आंकड़ा दर्शाता है कि बेरोजगारी प्रमुख चुनावी मुद्दा रहेगा, क्योंकि यह सीधे तौर पर देश की युवा आबादी और उनके भविष्य की संभावनाओं को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, शिक्षा व्यवस्था और महँगाई भी जनता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय बने हुए हैं। सामाजिक समरसता, विशेष रूप से जातिगत और सांप्रदायिक तनावों के संदर्भ में, एक और बड़ा चुनावी मुद्दा है, क्योंकि देश में सामाजिक सौहार्द बनाए रखना लोकतंत्र की स्थिरता के लिए आवश्यक है। इन सभी कारकों को देखते हुए, 2024 का चुनाव न केवल राजनीतिक दलों के लिए बल्कि देश के सामाजिक और आर्थिक स्थिति को आकार देने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण होगा।

राजनीतिक दलों की रणनीतियां और गठबंधन

2024 के लोकसभा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों की रणनीति और गठबंधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भाजपा और कांग्रेस के अतिरिक्त तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना और आम आदमी पार्टी की जैसे क्षेत्रीय दल भी सक्रिय है। 2019 के चुनावों के बाद विपक्षी गठबंधन कमजोर नजर आया, जबकि भाजपा ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। आगामी चुनावों में विपक्षी दलों के लिए एकजुट रहना आवश्यक होगा। हाल के विधानसभा चुनावों और 2019 नतीजों को देखते हुए गठबंधन राजनीति का स्वरूप बदल रहा है, जो चुनावी परिणामों को प्रभावित करेगा और सरकार के गठन की दिशा तय करेगा।

वोटिंग पैटर्न और जनादेश की दिशा

लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान के बदलते रुझान एक महत्वपूर्ण विषय हैं। हाल के वर्षों में भारत में युवाओं और महिलाओं की मतदाता के रूप में भागीदारी बढ़ी है, जिससे चुनावी नतीजों पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। 2019 के आम चुनाव में कुल 65.9% मतदान हुआ था, जिसमें

18–25 आयु वर्ग के युवाओं का मतदान 30% तक बढ़ा थाद्य यह संकेत देता है कि आगामी चुनावों में युवा मतदाताओं एक निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।

इसके अलावा, विभिन्न राज्यों में मतदान पैटर्न में भी बदलाव देखने को मिले हैं। कुछ राज्यों में महिला मतदाताओं की भागीदारी पुरुषों से अधिक रही है, जो राजनीतिक दलों की रणनीतियों को प्रभावित कर सकती है। पार्टियों ने भी अपने चुनावी योजनाओं में युवा और महिला मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनायी है। इन कारकों के आधार पर, 2024 के चुनावों में मतदाता समूह को बढ़ता प्रभाव जनादेश की दिशा को बदल सकता है और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को एक नई दिशा में ले जा सकता है।

किसे मिलेगा जनादेश?–सम्भावनाएँ और भविष्यवाणियाँ

1.BJP और NDA का भविष्यः भारतीय जनता पार्टी (BJP) और उसकी सहयोगी पार्टियों का गठबंधन (छक।) 2014 और 2019 के लोक सभा चुनावों में शानदार सफलता प्राप्त कर चुका है। 2024 में भी BJP के लिए यह गठबंधन एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। हालाँकि, कुछ दलों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अगर यह गठबंधन मजबूती से चुनावी मैदान में उतरे BJP एक बार फिर सत्ता में आ सकती है।

BJP ने हमेशा अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को एक मजबूत नेता के रूप में प्रस्तुत किया है, जो देश की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। आगामी चुनाव में यही छवि और उसकी लोकप्रियता ठश्रच के पक्ष में काम कर सकती है। हालाँकि, BJP को विपक्षी दलों से कड़ी चुनौती मिल सकती है जो उनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं।

2. विपक्षी एकजुटता और नई राजनीतिक हलचलरू विपक्षी दलों के लिए यह चुनाव एक चुनौतीपूर्ण अवसर होगा, क्योंकि उन्हें अपने आंतरिक एकजुटता बनाए रखनी होगी। कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों के बीच गठबंधन की संभावनाओं को लेकर कुछ चर्चाएँ चल रही है। अगर विपक्षी दल अपने मतभेदों को भुलाकर एकजुट होते हैं तो वे BJP के खिलाफ प्रभावी चुनावी अभियान चला सकते हैं।

कांग्रेस, समाजवादी पार्ट, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे दल यदि चुनावी गठबंधन बनाते हैं, तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है।

3. नई राजनीति और क्षेत्रीय दलों की भूमिकारू भारत में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। 2024 में ये दल राष्ट्रीय राजनीति में अपनी स्थिति को और सुदृढ़ करने का प्रयास करेंगे। राज्यों में अपनी सुदृढ़ पकड़ रखने वाले ये दल राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका को बढ़ा सकते हैं। यह भी संभव है कि कुछ नए दलों के उभरने से चुनाव परिणाम पर प्रभाव।

लोक सभा 2024 को चुनाव भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में निर्णायक मोड़ सिद्ध हो सकता है। ये चुनाव न केवल आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर जनता की चिंताओ का प्रतिबिम्ब होगा किंतु यह भारत की बदलती चयन मानसिकता व आकांक्षाओं को भी उजागर करेगा।

बेरोजगारी, महँगाई व आर्थिक असमानता जैसे मुद्दे जनसाधारण के दिलों–दिमाग में गहरे स्थान पर है, और उनका समाधान ही आगामी चुनावों के परिणामों को प्रभावित करेगा।

युवाओं की बढ़ती जागरूकता व सोशल मीडिया का प्रभाव इस बार के चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगे। राजनीतिक दलों के लिए यह समय अपनी नीतियों को जनता तक सही ढंग से पहुँचाने और उनके वास्तविक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का है। धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे भी चुनावी रणनीतियों को अकार देंगे और इनका प्रभाव परिणामों पर स्पष्टता से दिखेगा।

विपक्षी दलों की एकजुटता और क्षेत्रीय दलों की बढ़ती भूमिका भी चुनावी प्रदेश को प्रभावित कर सकती है। साथ ही अगर महँगाई और जीवन यापन के मुद्दों पर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है, तो यह विपक्ष के लिए एक सुनहरा अवसर सिद्ध हो सकता है।

कुल मिलाकर लोक सभा 2024 का चुनाव भारतीय राजनीति में बदलाव विकास और चुनौतियों का प्रतीक बनेगा। यह लोकतंत्र की ताकत और विविधता को दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण अवसर होगा जो भारतीय राजनीति की नई दिशा तय करेगा।

संदर्भ सूची

https://theisrm.org/en/general-elections-in-india-2024-significance-implications

https://www.financialexpress.com/opinion/2024-lok-sabha-election-a-return-to-democracy/3514570/lite/

https://indianexpress.com/elections/state-wise-winner-list-lok-sabha-elections-2019-5739099/#

https://en.m.wikipedia.org/wiki/2019_Indian_general_election

https://inc.in/congress-sandesh/national/india-opposition-parties-alliance-for-2024

https://www.thehindu.com/elections/lok-sabha/lokniti-csds-2024-pre-poll-survey-jobs-inflation-key-issues-in-2024-lok-sabha-elections/article68051581.ece/amp/

https://en.m.wikipedia.org/wiki/CVoter

https://www.reuters.com/world/india/indias-lok-sabha-election-2024-what-are-key-issues-2024-04-15/

Aiming High, Touching Sky

सी जी एस

वैश्विक अध्ययन केंद्र

(पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र)

अकादमिक अनुसंधान केंद्र भवन

गुरु तेग बहादुर मार्ग

दिल्ली विश्वविद्यालय

दिल्ली– 110007

www.cgs.du.ac.in @cgsofficialdu office@cgs.du.ac.in +91-11-27666281